(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सम्भावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) जी नहीं । "भेल एक लाभ कमाने वाली कंपनी है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान "भेल का लाभ और कारोबार इस प्रकार रहा :

(करोड़ रुपए लगभग)

	1990-91	91-92	92-93
कर पूर्व लाभ	201	187	309
कारोबार	3154	3331	3508

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3172. **श्री प्रदीप जोगी**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रक के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ उपक्रम इंजीनियरी क्षेत्र में भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इंजीनियरी क्षेत्र में ऐसे उपक्रम स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चल रहे सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों की इकाइयों के राज्य/संघ, राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र सं. 61]

(ख) और (ग) 28 सरकारी उपक्रम इंजीनियरी क्षेत्र में हैं। ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं ।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरी प्रभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची ।

1. एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3. बर्न स्टण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड
4. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड
5. रेरोल बर्न लिमिटेड
6. जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड
7. बेथवट एण्ड कम्पनी लिमिटेड
8. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
9. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंस लिमिटेड
10. बेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड
11. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड
12. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड
13. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसरस लिमिटेड
14. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
15. त्रिवणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
16. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टसलिमिटेड
17. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
18. एच. एम. टी. लिमिटेड
19. इन्स्ट्रूमेन्टशन लिमिटेड
20. साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
21. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
22. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
23. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

24. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

25. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

26. प्रागा टूल्स लिमिटेड

27. एच. एम. टी. बियरिंग्स लिमिटेड

28 राजस्थान इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

DUTCH INVESTMENT PROPOSAL IN INDIA

3173. SHRI MOHINDER SINGH LATHER : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a leading Dutch Company accompanying Dutch Prime Minister during his recent visit to the country had shown interest to invest in India ;

(b) if so, what are the areas in which the Dutch Company showed their interest to invest, stating the conditionalities, if any, proposed by the Dutch delegation ; and

(c) the reaction of Government with regard to the proposal made by the Dutch delegation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (c) Yes, Sir. Several of the Companies who accompanied the Dutch PM to India had expressed general interest in investing in India. This include activity/Jt. ventures in the fields like Dredging, Consultancy, Defence electronics, Food processing, Telecommunication, Banking and Insurance Services, etc. In Government of India's interaction with the Dutch, the Government welcomed their interest.

PROBLEMS OF STOCK-PILING IN CEMENT INDUSTRY

3174. SHRI DIGVIJAY SINGH : SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the situation of stock piling and curtailment of production in the Cement Industry in the country ;

(b) if so, what are the major problems being faced by the Cement Industry leading to such a situation ; and

(c) what measures are contemplated by Government to retrieve the Cement Industry from the difficulties faced by it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) and (b) The actual production of cement by large cement plants was 34.38 million tonnes during the period April-November in 1993-94 as against 32.81 million tonnes during the corresponding period in 1992-93. Production, despatch, stock of cement and clinker, etc. have been showing a varying trend from month to month during 1993-94. There is a slight increase in stock during the later part of the current year.

(c) Cement Industry has been de-licensed. All price and distribution controls have been lifted with effect from 1st March, 1989. Therefore, the demand and supply of cement, price etc. are determined by the interplay of market forces. However, Government provides all infrastructural support to the Cement Industry such as supply of coal and wagons on priority basis.